

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 82/2017

1. लक्ष्मण पुत्र मोती जाति गुर्जर निवारी भदलाव तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर।
2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, सवाई माधोपुर।

रेस्पोंड

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर।  
मु०न० 07/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी० की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पोंड की ओर से पैराकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 08.03.2021

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 07/2012 डिक्री एवं निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 बाबत इस्तकाररहक स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरुस्ती इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलांट को दिनांक 10.11.1975 को खसरा नम्बर 520/1 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भदलाव की भूमि आवंटन होकर उसको 10.11.1975 को कब्जा दिया गया था और वादी/अपीलांट के हक में पट्टा जारी किया गया था तब से वादी/अपीलांट इस आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा वादी/अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जमाबंदी सम्वत 2043-46 में वादी/अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। वर्ष 1997 के आस पास ग्राम भदलाव में सहायक भू प्रबंधक अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 520/1 रकबा 05 बीघा का भू प्रबंधक विभाग द्वारा सर्वे किया गया जिसमें इस आराजी के नवीन नम्बरान, खसरा नम्बर 1068 व 1069 बनाये जाकर वादी/अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 520/1 का रकबा खातेदारी की जगह चारागाह दर्ज कर दिया गया जबकि भू प्रबंधक विभाग को इस सम्बन्ध में खातेदारी तब्दील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी बगैर किसी नोटिस एवं सुनवाई किये बिना ही गुप्त रूप से मनमर्जी से इस भूमि की किरम तब्दील कर दी जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। वादी/अपीलांट विवादित आराजीयात के नवीन ख०न० 1068 व 1069 पर लगातार बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। वादी/अपीलांट के पुराने खसरा नम्बर 520/1 का नवीन नम्बर खसरा नम्बर 1068



1069 बना दिया गया है और अब इस भूखण्ड खसरा नम्बर को चारागाह बता दिया गया है जिसके कारण प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट अनावश्यक रूप से तंग व परेशान कर रहे हैं तथा प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट संख्या 01 जबरदस्ती बेदखल करने पर उत्तारू है। वादी/अपीलांत को यह एक हासिल है कि वह प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट को हुजूम इकतानाई दवागी से पाबंद करावे कि वह उसकी विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1068 व 1069 का इन्द्राज कमरा 0.67 एकर एवं 1.17 हेक्टर में एक हेक्टर 25 एकर भूमि का इन्द्राज वादी/अपीलांत के नाम वतीर खातेदार बना करे। बिनाय दावा व बिनाय मुखारमत दिनांक 08.04.2005 को बयोन लेने नकल जमाबंदी उस समय मालूम हुई तब इस इन्द्राज का पता लगा। इसलिये दावा वादी/अपीलांत बयोन इत्तम इन्द्राजात बिनाय दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत किया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी/अपीलांत विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट डिक्री फरमाया जावे व वादी/अपीलांत को उक्त खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार इन्द्राज जमाबंदी में किये जावे। प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी/अपीलांत के वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत बेजा न तो स्वयं करे न ही किसी दीगर से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांत द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अपीलांत एडवोकेट व परोकार सरकार की सुनी गई।

3. अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में, अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के विपरीत होने से मंसूख किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत ने दिनांक 24.05.2005 को राजस्व दावा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटी0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के बयान लिये बिना ही दिनांक 24.05.2017 को राजस्व अभियान कैम्प बदलाव में निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रेषित मौके की रिपोर्ट पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में अहम भूल की है। अपीलांत को वाके ग्राम बदलाव में दिनांक 10.11.1975 को साबिक खसरा नम्बर 520/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि चारागाह से सिवायचक में तब्दील करते हुए आवंटन की गई थी, जिस पर अपीलांत का आवंटन से लेकर आज तक भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक खसरा नम्बर 520 का रकबा बहुत बड़ा रकबा था। अपीलांत के साथ किशोर खटीक, गंगाविशन खटीक, रामजीलाल खटीक, मोतीलाल बैरवा, हजारी बैरवा को भी आवंटन हुई थी। साबिक खसरा नम्बर 520 की ट्रेसशीट में तरमीम नहीं होने के कारण भू प्रबंधक विभाग ने मौके पर गये बिना

ही नवीन रिकॉर्ड तैयार किया है। भू प्रबंधक विभाग ने अपीलान्ट के कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर 1069 रकबा 1.07 है० को राजस्व रिकार्ड में चारागाह में दर्ज कर दिया जबकि मौका देखे बिना ही अपीलान्ट के नाम से हाल खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 है० दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट का हाल खसरा नम्बर 285 पर भौतिक कब्जा भी नहीं है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं किया है। अपीलान्ट के कब्जे की भूमि के आस पास की भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 1.25 है० रामजीलाल खटीक की, खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.25 है० मोती पुत्र दीना बंजारा की, खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.41 है० किशोर पुत्र छोटया गुर्जर के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के गवाहान के बयान लिये बिना ही एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही निर्णय करके अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 07.09.2017 को न्यायालय में तारीखों की जानकारी करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावे। वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाई माधोपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.67 है० खसरा नम्बर 1069 रकबा 1.07 है० में से रकबा 1.25 है० अपीलान्ट के नाम से खातेदारी में दर्ज की जाकर अपीलान्ट के नाम से दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 है० को चरागाह में दर्ज की जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट की ओर से परोकार सरकार ने जबाब बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1068 व 1069 वाके ग्राम भदलाव में चारागाह राजस्व रिकार्ड में अंकन है जो धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है जिसकी खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। दफा-5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधिपूर्वक अपीलान्ट निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. अपीलान्ट अभिभाषक व परोकार सरकार द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण के परीक्षण से सुस्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2069-72 वाके ग्राम भदलाव के खाता संख्या 265 के अनुसार खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 हैक्टर लक्षमना पुत्र मोती जाति गूजर के नाम अंकित है। क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र, भू प्रबंधक विभाग ग्राम भदलाव के अनुसार खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 है0 का साबिक नम्बर 520 है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2043 ल0 2046 वाके ग्राम भदलाव के खतौनी संख्या 221 पर खसरा नम्बर 520/1 रकबा 5 बीघा लक्षमना पुत्र मोती गूजर के नाम अंकित है। सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति के अनुसार लक्षमन पुत्र मोती जाति गूजर निवासी भदलाव को खसरा नम्बर 520/1 का आवंटन किया गया है। अपील भीमो में खसरा नम्बर 285 के स्थान पर खसरा नम्बर 1068 व 1069 को अपीलार्थी के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से सम्वत् 2077 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1069 रकबा 1.07 साबिक खसरा नम्बर 520/8 मि. से बनना स्पष्ट है। खसरा नम्बर 1069 व 1068 चारागाह में अंकित है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, जिसको अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2017 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर के मु0नं0 07/2012 निर्णय दिनांक 24.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 08.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*(Handwritten Signature)*

( बी0एल0रमण )

राजस्थान अर्पित प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर